आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 18.12.2024
समय 0720

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दूध, शहद, कृषि उत्पादन और बागवानी को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
- गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय संविधान को पिछडे वर्गों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का मूलभूत स्रोत बताया।
- शासन ने जल और सीवर के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफी की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाई।
- उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1 हजार 4 सौ 80 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायतित परियोजना को मंजूरी।
- **और,** प्रदेश सरकार ने सभी जिला पंचायतों को चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के रूप में 77 करोड 50 लाख की धनराशि जारी की।

टिहरी महोत्सव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध, मधु, कृषि उत्पादन और बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। टिहरी गढ़वाल में जौनपुर क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि होम स्टे के माध्यम से भी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास जारी है। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है।

मुख्यमंत्री ने टिहरी के गरखेत में स्थाई हैलीपेड का निर्माण और जौनपुर महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की भी घोषणा की।

केन्द्रोय गृह मंत्री

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय संविधान सरकार के लिए मात्र एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि पिछडे वर्गों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का मूलभूत स्रोत है। उन्होंने कहा कि संविधान देश में लोकतंत्र की जडें मजबूत करता है और बिना किसी रक्तपात के सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। राज्यसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मंत्री विपक्ष के इस आरोप का करारा जवाब दिया कि संविधान की अनदेखी की जा रही है। श्री शाह ने कांग्रेस शासन के दौरान किये गए अनेक संविधान संशोधनों का उल्लेख किया और बताया कि कांग्रेस के शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का पहला संविधान संशोधन हुआ था।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 16 वर्ष के शासन में केवल 22 बार संविधान संशोधन किये गए, जबकि कांग्रेस के 55 साल के शासन में 77 संशोधन किए गए। श्री शाह ने कहा कि आज देश विश्व की पांचवीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था है।

समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करने की बात का ज़िक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये भाजपा सरकार की अपने वादे के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

आरपीएफ

रेलवे सुरक्षा बल– आरपीएफ के समन्वय से राजकीय रेलवे पुलिस– जीआरपी के प्रमुखों का पांचवां अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रेलवे मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इस सम्मेलन ने यात्री सुरक्षा, अपराध कम करने की रणनीतियों तथा रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण जनशक्ति की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों तथा सुरक्षा अधिकारियों को एक मंच प्रदान किया।

इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जीआरपी और आरपीएफ के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया।

आपदा प्रबन्धन

केन्द्र सरकार ने उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ और रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से 1 हजार 4 सौ 80 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायतित परियोजना को मंजूरी दी है।

इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई इस धनराशि से राज्य में आपदा के समय आपदा राहत और बचाव कार्यों के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने में इससे बड़ी मदद मिलेगी।

इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 8 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण और अन्य कार्य किए जाएंगे।

सरचार्ज माफी

उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के जल और सीवर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जल और सीवर के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफी की अवधि को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने बीते नवंबर माह में जल और सीवर के अवशेष देयकों का 31 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान किए जाने पर विलंब शुल्क की धनराशि को शत प्रतिशत माफ करने की घोषणा की थी। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया है।

धनराशि जारी

प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के अन्तर्गत सभी जिला पंचायतों को चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के रूप में 77 करोड 50 लाख की धनराशि जारी कर दी है।

शासन ने पिथौरागढ विधानसभा में इमला से इमलाधुरा तक संपर्क मार्ग के क्रियान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 56 लाख 03 हजार रुपये की मंजूरी दी है। साथ ही धारचूला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

वहीं, बागेश्वर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 50 लाख 09 हजार धनराशि स्वीकृति की गयी है।

जमरानी बांध परियोजना

कुमाऊं मंडल में निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना वर्ष 2029 तक बनकर तैयार होगा। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने बांध के निरीक्षण के दौरान ये जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि 1 सौ 50 मीटर ऊंचा और 10 किलोमीटर लंबा ये बांध 3 हजार 700 करोड़ की लागत से बन रहा है। श्री रावत ने कहा कि बांध के निर्माण से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में गर्मियों के दिनों में होने वाली पेयजल किल्लत की समस्या का समाधान हो जाएगा।

प्रशासक नियुक्ति

बागेश्वर में क्षेत्र और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्षेत्र पंचायतों में निवर्तमान प्रमुख तथा ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने आदेश जारी किया है। नियुक्त प्रशासक सामान्य रूटिंग कार्यों का निर्वहन करेंगे।

आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नजर———

एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में स्वीकार। इस खबर को आज सभी प्रमुख अखबारों ने प्राथमिकता दी है। अमर उजाला लिखता है– विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश करने के पक्ष में 269 और विरोध में 198 मत पड़े।

गृहमंत्री अमित शाह के हवाले से हिंदुस्तान लिखता है– धर्म के आधार पर आरक्षण कभी लागू नहीं होने देंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से अमर उजाला लिखता है– प्रदेश में पिछले साढे तीन साल में 19 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, कई पदों पर अब भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

31 लाख से अधिक जल और सीवेज उपभोक्ताओं को राहत, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण सहित इस खबर को प्रमुख अखबारों ने समाचार पत्र में स्थान दिया है।